राजनीति के केंद्र में शर्ट

मुखिया जी के चौपाल में काफी भीड है । सभी लोग टीवी पर आंख गड़ाए हुए हैं। वे संसद की कारवाई देख रहे हैं। उस भीड़ में चौपाल का खबरी पटवारी लाल भी मुडी नीचे कर बैठा हुआ है। वह टीवी पर आंख नहीं गड़ाया है किंतु सब कुछ सुन रहा है । विपक्ष का नेता राहुल गांध टी-शर्ट पहनकर संसद में हाजिर है। उन्हें देखकर लोकसभा स्पीकर झाला उठाते हैं। संसद में टी-शर्ट पहनकर आना किसी भी कोड से उचित नहीं है। लेकिन इसका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है किस परिधान मैं सदस्यों को संसद में आना है।तथा किस परिधान में नहीं आना है तो फिर शर्ट पर टोका टोकी क्यों? इतना सुनते ही पटवारी लाल आंख मलते हुए खांड हुआ और उसने कहा- मैं खुलासा करता हूं ऐसा क्यों हो रहा है ?

मोदी सरकार जब से सत्ताह में आई है और मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तब से गांधी परिवार की उपलब्धियां को नकारा जा रहा है। मोतीलाल से लेकर जवाहरलाल श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक के कामों को नकारने का सिलसिला? जारी है । ऐसा क्यों है आज तक मैं समझ नहीं पाया हू ?

किस कंपनी का टी-शर्ट बना है जीस टी-शर्ट का विज्ञापन राहुल गांधी कर रहे है?। इसी शर्ट को पहन कर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का प्रारंभ किया था। उनकी यह यात्रा साधारण यात्रा नहीं थी। यह यात्रा वास्तव में लॉन्ग मार्च की यात्रा थी। चीन का लोकप्रिय कम्युनिस्ट नेता ने भी लॉन्ग मार्च किया था और क्रांति का अलग जगा कर सारी गली व्यवस्था को नष्ट कर सत्ता पर कब्जा कर दिया था। राहुल जी का लॉनग मार्च का यही उद्देश्य तो नहीं है? राहुल को पप्पू साबित करने के लिए सत्ताधारियों ने कोई कोर कसर नहीं उठा रखा था ।लोग कहते हैं उन्हें पप्पू बनाने के लिए करोड़ों खर्च किया गया था । वह इसलिए की गांधी परिवार का यह चिराग कहीं जनता में लोकप्रिय हो गया तो सत्ता पर खतरा उत्पन्न कर सकता है। कुछ लोगों नेकहना शुरू किया पप्पू है पप्पू। दस कदम चलेगा हार कर बैठ जाएगा। लेकिन जब वह आगे बढ़ता गया तो जनता उसके पीछे गोल बंद होने लगी। वह इसी शर्ट को पहना था । धूप ताप इसी शर्ट पर आगे कदम बढ़ाए चला जा रहा है। इस टी-शर्ट में क्या है प्रकृति के किसी भी मौसम का प्रभाव पप्पू पर नहीं पड़ रहा है। यह जांच का विषय है टी-शर्ट में है क्या? सत्ता के कुर्सी पर बैठे कुछ लोगों का यह कमेंट था?

इतिहास इस बात का गवाह है देश के बड़े-बड़े योगियों ने जोग के बदौलत और अपनी साधना के बल पर अपने शरीर को तपाकर शरीर कोऐसा बना लेते थे कि उनके शरीर पर ठंडा गर्मी का कोई असर नहीं पड़ता था। यह घोर चिंता का विषय है । जहां एक ओर। पप्पू बनाने का अभियान चल रहा था तो राहुल कहीं कोई साधना में लीन तो नहीं था? तथा उन्होंने अपने शरीर को तपा लिया। अब जब पप्पू की लोकप्रियता बढ़ रही है और उनकी लोकप्रियता घट रही है जो लोकतंत्र के शीर्ष कुर्सी पर बैठे हुए हैं।

वर्तमान सत्ताधारियों की देश को गुलामी से मुक्त करने में कोई भूमिका नहीं थी। वे एक दिन के लिए भी जेल नहीं गए । कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने देश आजाद न हो अंग्रेजों के की गुलामी से इस काम में लगे हुए थे । दूसरी तरफ गांधी परिवार सत्ताधारियों के आंख में खटक रही है उसे गांधी परिवार के पंडित जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजी सरकार के जेलों में यातना के शिकार बने हुए थे । 13 वर्षों तक उन्होंने जेल के शिकंजों में अपना समय गुजरा था । सत्ता का सुख भोगने वाले कितने दिनों तक जेल काटे हैं ? शहादत की चादर ओढ़ी है। लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकतंत्र के कुर्सी पर बैठने के बाद देश को आधुनिक भारत बनाने का संकल्प लेकर उसे संकल्प को पूरा किया है । आज जब लोकतंत्र का ताना-बाना छीतरा ने का काम किया जा रहा है । सत्ता सुख भोगने वाले अपनी सत्ता को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने के लिए लोकतंत्र के पाए को ढाहने में लगे हुए हैं।वहां गांधी परिवार का सपूत लोकतंत्र की प्रतिष्ठा के लिए जी जान से लगहुआ है । लोकतंत्र के स्थापना के लिए सड़क पर निकल पड़ा है । उसकी लोकप्रियता अब लोगों को समझ में आ रही है ऐसे में टी-शर्ट को राजनीति का केंद्र क्यों बनाया जा रहा है। अरे भाई! राष्टीय एकता का मूल्य संविधान में अंकित है ।उन मूल्यों को क्यों नकारा जा रहा है। यह लोकतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है । पप्पू के शर्ट पर नहीं बल्कि उसके कथन पर विचार किया जाना चाहिए जो विचार लोकतंत्र को मजबूत करने का दिशा निर्देश है ।

अरविंद विद्रोही
बिरसानगर जॉन नंबर 2 रोड नंबर 2 जमशेदपुर 19
मोबाइल-8789 718 130

माननीयों के सवालों का नहीं मिला जवाब, जनता करती रही इंतजार

इंदौर। मप्र की 16वीं विधानसभा के पंचम सत्र यानि बजट सत्र में विधायकों ने बढ़-चढ़कर सवाल पूछे, लेकिन विडंबना यह है कि कई विभागों ने सवालों के जवाब देने में केवल खानापूर्ति की है। यानी जनता इंतजार करती रही और माननीयों के सवालों का जवाब नहीं दिया गया। विधानसभा का रिकॉर्ड बता रहा है कि 80 विधायकों के सवालों के जवाब में राजस्व विभाग ने बड़ी गफलत की। विभागों द्वारा विधानसभा को लिखकर भेज दिया गया है कि विस्तृत जानकारी परिशिष्ट में है। यह विधानसभा को भेज दी गई। लेकिन जब विधायक परिशिष्ट लेने पहुंचे तो उन्हें वो मिले ही नहीं। यानि विधानसभा पुस्तकालय के रिकॉर्ड में भी नहीं थे। विधानसभा ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। साथ ही डीओ लेटर लिखकर आपत्ति की है।

गौरतलब है कि मप्र विधानसभा के बजट सत्र में भले ही 9 बैठकें हुईं, लेकिन इस दौरान जिस तरह सदन की कार्यवाही बिना गतिरोध के चली, उससे एक बार फिर से मप्र की गरिमा लौटी है। मप्र विधानसभा का बजट सत्र भले ही छोटा था, लेकिन इस दौरान जिस तरह विधायी, वित्तीय तथा लोक महत्व के कार्य संपन्न हुए, उससे मप्र विधानसभा एक बार फिर 21 साल पुरानी परिपाटी पर लौटती नजर आ रही है। लेकिन विडंबना यह पहले की तरह इस बार भी विधायकों के सवालों की पूरी जानकारी नहीं दी गई है।

विधानसभा ने पूछा कारण

गौरतलब है कि मप्र में सहारा समूह की संपत्तियों की खरीद-फरोख्त हुई या नहीं, हुई तो किसने की, बेचने और खरीदने वाला - कौन है, किस नियम के तहत ऐसा हुआ, भूमि की कीमत कितनी थी और कलेक्टर गाइड लाइन क्या कहती है... आदि कई सवालों के साथ सरकारी जमीनों की मौजूदा स्थिति को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के ढेरों विधायकों ने विधानसभा में सवाल लगाए थे। लेकिन विभागों ने करीब 80 विधायकों के सवालों का पूरा जवाब नहीं दिया है। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने राजस्व विभाग से कहा है कि तत्काल सात दिन के भीतर व्यक्तिगत रूचि लेकर परिशिष्ट के साथ जानकारी भिजवाएं।

राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल का कहना है कि पत्र आया है। कुछ कलेक्टरों से जानकारी नहीं मिल थी। अब आ गई है। एक-दो दिन में विधानसभा को भेज दी जाएगी। यहां बता दें कि कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने ही पूछा था कि 2020 के बाद सहारा समूह की कितनी जमीनों के सौदे हुए। राजस्व विभाग की ओर से कह दिया गया कि जानकारी विधानसभा के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में है। जबकि वहां कोई दस्तावेज नहीं था। कई दूसरे विधायकों के साथ भी ऐसा ही हुआ।

8 साल पुराने सवालों के जवाब अब तक नहीं

मप्र विधानसभा में आठ साल पहले मंत्रियों की ओर से सवाल के जवाब देने के लिए दिए गए आश्वासन अभी तक पेंडिंग हैं। अकेले जल संसाधन विभाग के ही 113 सवालों के जवाब में दिए गए आश्वासन पर सरकार की ओर से अभी तक विधानसभा को अवगत नहीं कराया गया है। इसमें वर्ष 2017 में दिए गए कई आश्वासन भी शामिल हैं। इसे देखते हुए अब विधानसभा सचिवालय ने जल संसाधन विभाग को लंबित आश्वासनों की सूची भेजी है और इसका जल्द से जल्द जवाब भेजने को कहा है। यह विभाग 2020 में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद से अब तक मंत्री तुलसी सिलावट के पास है। सवाल करने वाले कई विधायक 2018 का चुनाव हारने के बाद 2023 में फिर विधायक बन गए हैं जिसमें मुकेश नायक भी शामिल हैं। वहीं, कुछ विधायक पिछले चुनाव में हार के कारण अब पूर्व विधायक बन गए हैं।

इन सवालों के जवाब का इंतजार

पन्ना जिले में बांध टूटने के कारण और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच को लेकर विधानसभा में सवाल उठा था जिसमें ठेकेदार मेसर्स त्रिशूल कंस्ट्रक्शन जबलपुर से खर्च हुई राशि की वसूली होनी थी। इस मामले में सरकार ने विधानसभा में आश्वासन दिया था कि विभागीय जांच की जा रही है, और ठेकेदार के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही के लिए मुख्य अभियंता धसान केन कछार सागर द्वारा नोटिस जारी किया है। कार्यपालन यंत्री पन्ना ने सिरस्वाहा तालाब निर्माण का एग्रीमेंट अमान्य कर दिया है, और ठेकेदार से राशि की वसूली की जाएगी। फरवरी मार्च 2017 में विधानसभा सत्र के दौरान दिए गए मंत्री के आश्वासन का जवाब अब तक विधानसभा तक नहीं पहुंच सका है।

यह बांध 2016 की बारिश में टूटा था और चार गांवों की बस्तियां जल मग्न हो गई थीं। शहडोल जिले के ब्यौहारी तहसील के ग्राम बिजहा में दुधारिया नदी पर सिंचाई परियोजना में किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है लेकिन मुआवजा नहीं दिया है। किसानों की 70.181 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण का यह मामला पूर्व विधायक केदारनाथ शुक्ला ने मार्च 2017 के विधानसभा सत्र में उठाया था।

इसका जवाब भी विधानसभा को सरकार अब तक नहीं दे सकी है। पन्ना जिले में बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत बांध निर्माण और नहरों को बनाने में अनियमितता का मामला विधायक मुकेश नायक ने मार्च 2017 में उठाया था। मंत्री ने आश्वासन दिया था कि कार्यपालन यंत्री और अनुविभागीय अधिकारी व उपयंत्री को सस्पेंड किया है। उनकी विभागीय जांच चल रही है। इस मामले में आगे की कार्रवाई से विधानसभा को अवगत नहीं कराया है।

मुकेश नायक ने एक अन्य मामला पन्ना के बिलखुरा और सिरस्वाह बांध टूटने का उठाया था। जिस पर 2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और अफसरों पर कार्रवाई के बाद जानकारी देने के लिए कहा था। मार्च 2018 के सवाल पर दिए गए आश्वासन का जवाब अब तक विधानसभा को नहीं भेजा है। प्रदेश में सडक़ निर्माण के ई-टेंडर में हुई गड़बड़ी और अनियमितता का मामला विधायक हर्ष विजय गहलोत ने अगस्त 2021 में विधानसभा सत्र में उठाया था।

इस पर जांच जारी होने और कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने की जानकारी दी गई लेकिन इसके बाद आगे की कार्यवाही को लेकर दिए गए आश्वासन का जवाब विधानसभा नहीं पहुंचा है।

सवाल का जवाब देने में छूट गए पसीने

विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अधिकारियों के पसीने उस वक्त छूट गए। जब कांग्रेस विधायक के एक सवाल का जवाब तैयार करना था। पूर्व मंत्री और विधायक बाला बच्चा ने फूड एवं न्यूट्रीशियन सिक्योरिटी को लेकर सवाल पूछा था। जिसका जवाब देने के लिए अधिकारियों ने 7 बंडल का जवाब तैयार किया। जिसका वजन लगभग 50 किलो है। पूर्व मंत्री और विधायक बाला बच्चन ने सवाल पूछा था कि फूड एवं न्यूट्रीशियन सिक्योरिटी के तहत पिछले चार सालों में कितने जिलों में, कितने किसानों को 100 रुपए से 2 हजार रुपए तक की भुगतान राशि दी गई है।

इसके लिए हितग्राहियों के नाम, पता, प्रदान की गई राशि, बैंक का नाम सहित पूरी जानकारी मांगी गई थी। बाला बच्चन ने साथ ही एक और सवाल पूछा कि चार सालों में हितग्राहियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल की फोटोकॉपी विधानसभावार और जिलेवार दी जाए। क्योंकि कई मामलों में राशि प्रस्तुत किए गए बिलों के अनुसार बैंक अकाउंट में न देकर नगर दी गई।

इसकी जानकारी विधानसभावार मांगी गई है। विधायक के सवाल तैयार करने के लिए अधिकारियों को पौने 2 लाख कागजों की फोटोकॉपी कराकर जवाब दिया गया है।

मई से शुरू होंगे सहकारी समितियों के चुनाव

बारह साल बाद साढ़े चार हजार पैक्स के चुनाव

इंदौर। मप्र में वर्षों से भंग पड़ी प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों (पैक्स) के चुनाव की कवायद शुरू हो गई है। मई से इसकी शुरुआत होगी, जो सितंबर तक चलेगी। इनके चुनाव निपटने के बाद जिला सहकारी बैंकों के चुनाव करवाए जाएंगे।

प्रदेश की 4523 पैक्स में चुनाव ड्यू हैं। पैक्स के चुनाव काफी समय से लंबित हैं। अधिकतर सहकारी समितियों का कार्यकाल मार्च 2018 में खत्म हो चुका है। वहां पहले अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को ही कमान सौंप दी गई थी। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के दौरान कांग्रेस ने इस पर आपत्ति की, तो वहां सहकारिता विभाग ने अपने प्रशासक बैठा दिए। पहले विधानसभा और बाद में लोकसभा चुनाव के कारण इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए।

2013 में हुए थे पिछला चुनाव

गौरतलब है कि मप्र में पैक्स के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई है। मप्र राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी ने ये चुनाव 5 मई से सितंबर तक कराने का निर्णय लिया है। इससे पहले यह चुनाव 2013 में हुए थे और तब से अब तक पैक्स के चुनाव नहीं हो पाए थे। इसके लिए मतदाता सूची तैयार करने का काम तेजी से शुरू हो गया है। 14 मई को सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। मप्र राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी ने चुनाव कार्यक्रम एक साल पहले जारी किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते इसे टाल दिया गया था। अब, प्रदेश की 4531 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में अध्यक्ष और सदस्यों के चुनाव किए जाएंगे। यह चुनाव किसानों के जरिए किए जाते हैं।

चार चरणों में होंगे चुनाव

प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों (पैक्स) के चुनाव चार चरणों में होंगे और इस प्रक्रिया के तहत समितियों और बैंकों में संचालक मंडल का गठन किया जाएगा। वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले जबलपुर में चुनाव को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने दिसंबर 2023 में चुनाव कराने के निर्देश दिए, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण चुनाव प्रक्रिया में और देरी हुई। चुनाव न होने के कारण समितियों और बैंकों में नीतिगत निर्णय नहीं लिए जा पा रहे हैं। किसानों से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा, समितियों के विस्तार और कारोबार में भी निर्णय समय पर नहीं हो पा रहे हैं। प्रशासक केवल प्रशासनिक कामों पर ध्यान देते हैं, जिससे समितियों की प्रमुख गतिविधियों में देरी होती है। यह चुनाव पिछले कई वर्षों से लंबित हैं, लेकिन अब प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके तहत, 25 हजार से अधिक कर्मचारियों की जरूरत होगी, जिन्हें जीएडी से आदेश जारी कर चुनाव कराने के लिए नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा, चुनाव को सुचारू रूप से संचालन के लिए पुलिस बल की भी आवश्यकता होगी।

पैक्स में प्रशासक तैनात

चुनाव न होने के कारण, प्रदेश की लगभग 4531 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में फिलहाल प्रशासक कार्यरत हैं। इसी तरह प्रदेश के 38 जिला सहकारी बैंकों और अपेक्स बैंक में भी प्रशासक कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2013 में चुनाव के बाद पांच वर्ष के लिए संचालक मंडल ने काम किया। इसके बाद वर्ष 2018 में चुनाव होना था, लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते पैक्स चुनाव टल गया। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव आ गया। इसके बाद कांग्रेस सरकार चुनाव की तैयारी करा रही थी, फिर सरकार गिर गई। वर्ष 2020 में कोरोना आ गया, इसके बाद निकाय चुनाव शुरू हो गए।

वर्ष 2023 में चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई। कोर्ट ने दिसम्बर 2023 में सरकार को चुनाव कराने के निर्देश दिए। इसके बाद फिर अलग-अलग कारणों से चुनाव टल गए।

प्रभार से मुक्त होंगे एसीएस-पीएस

- मप्र में एक और बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी

- कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी

इंदौर। मप्र में आने वाले दिनों में एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी चल रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन के बीच सहमति बन गई है। जानकारी के अनुसार इस बड़ी प्रशासनिक सर्जरी में सबसे पहले अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों से प्रभार वाले विभाग लिए जाएंगे और उनकी जिम्मेदारी कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को दी जाएगी। गौरतलब है कि 12 बड़े विभागों का प्रभार एसीएस और पीएस के पास है।

मंत्रालयीन सूत्रों के अनुसार प्रदेश में होने वाली बड़ी प्रशासनिक सर्जरी में करीब 32 आईएएस को सरकार नई जिमेदारी देने की तैयारी में है तो प्रभार में टिके मंत्रालय के कई विभागों को स्वतंत्र अफसर भी मिलेंगे। सरकार ने इस फेरबदल में बीते एक साल के दौरान एसीएस, पीएस, सचिव, संभागायुक्त व कलेक्टरों के कामों को आधार बनाने की योजना रखी है। इसमें ऐसे अफसर जिनके काम के नतीजे अच्छे रहे हैं और सरकार को केंद्र स्तर पर, 16वें वित्त आयोग की प्रजेंटेशन बैठक में व अन्य स्तरों पर सराहना मिली, उनको बड़ी जिमेदारी दे सकती है। वहीं किरकिरी कराने वालों की कुर्सी खिसकना तय है।

कई महत्वपूर्ण विभाग प्रभार पर

मप्र में कई महत्वपूर्ण विभाग प्रभार पर चल रहे हैं। सूत्रों की मानें तो सरकार जल्द ही राज्य को स्वतंत्र कृषि उत्पादन आयुक्त और कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष देने की तैयारी में है।

वर्तमान में कृषि उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार वन विभाग के एसीएस अशोक बर्णवाल के पास है और कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त दायित्व सामान्य प्रशासन विभाग के एसीएस संजय दुबे के पास है, जबकि पीडब्ल्यूडी जैसे 12 बड़े विभागों का काम भी प्रभार पर चल रहा है। हो बड़े विभाग प्रभार पर हैं उनमें लोक सेवा प्रबंधन डॉ. राजेश राजौरा, एसीएस,

सीएमओ, कृषि उत्पादन आयुक्त अशोक बर्णवाल, एसीएस वन, कर्मचारी चयन मंडल संजय दुबे, एसीएस, जीएडी, विमानन संजय शुक्ला, एसीएस, नगरीय विकास एवं आवास, पीडब्ल्यूडी नीरज मंडलोई, एसीएस, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा संदीप यादव, पीएस, लोक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, आनंद विभाग राघवेंद्र सिंह, पीएस, औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन, विज्ञान एवं तकनीकी संजय दुबे, एसीएस, जीएडी, संसदीय कार्य अनुपम राजन, एसीएस, उच्च शिक्षा, मप्र राज्य लोक संपत्ति अनिरुद्ध मुकर्जी, एसीएस लोक संपत्ति प्रबंधनप्रबंधन कंपनी, भोपाल, विशेष आयुक्त समन्वय रश्मि अरुण शमी, एसीएस, खाद्य नागरिक मध्यप्रदेश भवन दिल्ली आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश धार्मिक शिवशेखर शुक्ला, पीएस, संस्कृति एवं पर्यटनट्रस्ट एवं बंदोबस्ती, पिछड़ा वर्ग एवं डॉ. ई. रमेश कुमार, पीएस अनुसूचित जाति अल्पसंयक कल्याण कल्याण, आयुष विभाग डीपी आहूजा, पीएस, मछुआ कल्याण, मत्स्य विकास, कुटीर/ग्रामीण उद्योग अमित राठौर, पीएस वाणिज्यक कर, पशुपालन एवं डेयरी उमाकांत उमराव, पीएस, खनिज संसाधन, एन्को नवनीत मोहन ठाकुर, पीएस, पर्यावरण विभाग, सामान्य प्रशासन एम सेलवेंद्रन, सचिव किसान कल्याण एवं कृषि कार्मिक विकास विभाग है।

शिकायत वाले अधिकारी भी हटेंगे

जानकारों का कहना है कि इस बार के तबादले में अफसरों की परफॉर्मेंस देखी जाएगी। वहीं जनप्रतिनिधियों की तरफ से जिन अधिकारियों की सरकार को शिकायत मिली उन पर गाज गिरना तय माना जा रहा है।

वहीं प्रदेश के कुछ जिलों के कलेक्टर व संभागों के संभागायुक्त भी बदले जाने हैं। इस बदलाव के कई आधार होंगे। जिनमें जिलों में घटित होने वाली बड़ी घटनाओं को नहीं संभाल पाना, प्रशासनिक चूक के कारण घटना होना, नेताओं की वास्तविक नाराजगी का बार-बार सामने आना, खनिज माफिया व अपराधियों की करतूतें उजागर होना, अलग-अलग स्तर पर कमियों के कारण विपक्ष को मुद्दा मिलना, जैसे बिंदू अहम हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने ऐसे कुछ बिंदुओं के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है।

प्रदेश में अधिकारियों को नई जिम्मेदारी देने के लिए अब तक के उनके काम को देखा जाएगा। इसमें मंत्रालय में विभाग अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव से लेकर, उप सचिव से लेकर विभाग प्रमुख और संभाग और जिलों में पदस्थ अधिकारियों के ट्रांसफर होंगे।

कटाक्ष

व्यापार नहीं

ये सल्तनत है साहिब
आपका व्यापार नहीं
सब यहीं रह जाएगा
नाम लेगा कोई नहीं।

अकड़

मालूम नहीं कब जाएगी
आपकी ये दिमाग़ी जकड़
याद रहे मगर
टूट जाते हैं लोग अक़्सर
होती है जब हद से ज़्यादा
अकड़।

गाँव-शहर

गाँव बदलता नहीं
शहर बन जाता है
शहर बनता नहीं
गाँव छूट जाता है।

ग़ुलामी

बड़ा अभिमान था
उन्हें अपनी आज़ादी पर
रक्खा है जब से अंग रक्षक
एहसास होने लगा है ग़ुलाम-सा।

वीरेन्द्र नारायण झा
झंझारपुर-बिहार।